TEACHERS OF BIHAR
THE CHANGE MAKERS

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

सुरक्षित बचपन अभियान

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान

जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण – हर बच्चे का अधिकार



रिया और रिंकू के साथ

सुरक्षा, सम्मान और हिम्मत की कहानी

हर बच्चे का बचपन, हम सबकी ज़िम्मेदारी...

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल महसूस करने का अधिकार है। लेकिन कभी-कभी बच्चों को अपने आसपास किसी गलत या असुरक्षित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।

POCSO अधिनियम, 2012 क्या है?

ऐसी परिस्थितियों से बच्चों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष कानून बनाया, जिसे **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** कहा जाता है।

यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की बात सुनी जाए, उन पर विश्वास किया जाए और उन्हें सहयोग मिले।

POCSO अधिनियम बताता है कि कौन-से व्यबहार यौन अपराध माने जाते हैं, बच्चे इसकी शिकायत कैसे कर सकतेहैं, और यह प्रक्रिया बच्चों के अनुकूल, गोपनीय और संवेदनशील हो।



रिया: रिंकू, क्या तुम्हें पता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून है?

रिंकू: सच में? उसका नाम क्या है?

रिया: इसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या POCSO अधिनियम कहते हैं।

आपका शरीर, आपका अपना है

रिया और रिंकू व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं।



हमारा शरीर व्यक्तिगत है। बच्चे से जुड़ा कोई भी यौन स्पर्श या व्यवहार **POCSO अधिनियम, 2012** के अंतर्गत अपराध है।

किसी बच्चे को असुरक्षित स्पर्श के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और न ही उसे बहलाया जाना चाहिए।

सुरक्षा के नियम

- **नहीं कहें**
- **वहाँ से दूर जाएँ**
- **किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएँ**

POCSO अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध

POCSO अधिनियम बच्चों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों को पहचानता है।

यौन अपराध

- प्रवेशात्मक यौन हमला
- गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला
- यौन हमला
- गंभीर यौन हमला
- यौन उत्पीड़न
- अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग
- बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री का संग्रहण।

अन्य अपराध

- किसी मामले की सूचना न देना या रिकॉर्ड न करना
- झूठी शिकायत या गलत जानकारी देना
- बच्चे की पहचान प्रकाशित करना या उजागर करना।



यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

विभिन्न अपराध और उनके दंड

सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार है।

अपराध	अर्थ	दंड
1 **प्रवेशात्मक यौन हमला (धारा 3, 4)**	शरीर के किसी भी भाग में लैंगिक उद्देश्य से प्रवेश करना, जिसमें यौन अंग, गुदा, मुंह आदि में किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग का प्रवेश शामिल है।	न्यूनतम **20 वर्ष** का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
2 **गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला (धारा 5, 6)**	लैंगिक उद्देश्य से प्रवेश करना जब अपराध किसी लोक सेवक, शिक्षक, रिश्तेदार, अभिभावक या किसी विश्बास में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए, या सामूहिक रूप से, या हथियार के उपयोग से, आदि।	न्यूनतम **20 वर्ष** का कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
3 **यौन हमला (धारा 7, 8)**	बच्चे के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध यौन प्रकृति का शारीरिक संपर्क, जैसे शरीर के किसी भी भाग को छूना, बच्चे को यौन उद्देश्य से छुड़वाना या अन्य कोई असंवैधानिक अनुचित संपर्क।	न्यूनतम **3 वर्ष** का कारावास, जिसे **5 वर्ष** तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
4 **गंभीर यौन हमला (धारा 9, 10)**	ऐसी परिस्थितियों में यौन हमला, जिनमें लोक सेवक, शिक्षक, रिश्तेदार या विश्बास के पद पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा, सामूहिक रूप से, बार-बार या अन्य गंभीर परिस्थितियों में किया गया यौन संपर्क शामिल है।	न्यूनतम **5 वर्ष** का कारावास, जिसे **7 वर्ष** तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
5 **यौन उत्पीड़न (धारा 11, 12)**	बच्चे के प्रति अश्लील संकेत करना, यौन उद्देश्य से कोई टिप्पणी करना, अश्लील सामग्री दिखाना या अन्य कोई अनुचित यौन व्यवहार करना।	न्यूनतम **1 वर्ष** का कारावास, जिसे **3 वर्ष** तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।



POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रमुख अधिकारी

सुरक्षित बचपन के लिए मिलकर काम करते हुए



विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)

- POCSO अधिनियम के अंतर्गत अपराध की शिकायत प्राप्त करती है।
- प्राथमिकी (FIR) दर्ज करती है और बाल-अनुकूल जाँच करती है।
- बच्चे की सुरक्षा, निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करती है।



बाल कल्याण समिति (CWC)

- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण सुनिश्चित करती हैं।
- आवश्यकतानुसार अस्थायी आश्रय, परामर्श और अन्य सहायता उपलब्ध कराती है।



विशेष न्यायालय

- POCSO अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई करता है।
- बच्चे की पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए बंद कमरे में (इन-कैमरा) कार्यवाही करता है।
- यथासंभव एक वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा करने का प्रयास करता है।



सहायक व्यक्ति

- बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार बच्चे और उसके परिवार को जाँच तथा मुकदमे की प्रक्रिया में सहायता और भावनात्मक समर्थन देता हैं।



विशेष लोक अभियोजक

- विशेष न्यायालय में अभियोजन का संचालन करता है।
- बच्चे के पक्ष में सशक्त और संवेदनशील तरीके से मामला प्रस्तुत करता है।
- बच्चे को न्याय दिलाने में सहायता करता है।

बच्चों के लिए सुरक्षित इंटरनेट

क्लिक करने से पहले सोचें



एक दिन रिंकू एक टैबलेट पर संदेश देख रहा था, तभी उसे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आया।



रिंकू: रिया, एक अनजान व्यक्ति मुझसे मेरी फोटो मांग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?



रिया: ऐसा नहीं करना चाहिए, रिंकू। ऑनलाइन अनजान लोगों के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी या निजी तस्वीरें कभी साझा नहीं करनी चाहिए।



रिंकू: और अगर कोई लगातार मुझे अजीब या अयुयुचित मैसेज भेजता रहे तो क्या करें?



रिया: उनसे बात करना बंद कर दो, यदि संभव हो तो उनके संदेशों के स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताओ।

इंटरनेट उपयोगी और मनोरंजक हो सकता हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वे क्या साझा करते हैं और किससे बात करते हैं।

क्या न करें

- अपना पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम या पासवर्ड साझा न करें।
- अनजान लोगों के साथ अपनी निजी तस्वीरें या वीडियो साझा न करें।
- ऑनलाइन केवल दोस्त बनने के लिए किसी अनजान व्यक्ति से न मिलें।
- ऐसे संदेशों का जवाब न दें जो आपको असहज महसूस कराएँ।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें या अनजान लोगों के रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।



यदि कोई आपको ऑनलाइन असहज महसूस कराए तो

- उससे बातचीत तुरंत बंद कर दें।
- यदि संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले लें।
- अपने माता-पिता, शिक्षक, अभिभावक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताएं।
- उस व्यक्ति को ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें।
- आवश्यक हो तो तुरंत मदद माँगें।

रिया और रिंकू कहते हैं –

"क्लिक करने से पहले सोचें।
अगर कुछ गलत लगे, तो ऑनलाइन साझा न करें और किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताएं!"

रिपोर्ट करें • सुरक्षा करें • रोकथाम करें

ऑनलाइन सुरक्षा ही बाल सुरक्षा है

चेतावनी संकेतः

एक बच्चे को मदद की आवश्यकता हो सकती है







कभी-कभी बच्चे स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते कि कुछ गलत है।
व्यवहार में बदलाव इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे को मदद की आवश्यकता है।

इन संकेतों पर ध्यान दें:



असामान्य रूप से चुप रहना
या अपने आप में रहना



कुछ विशेष लोगों या
स्थानों से डरना



अचानक गुस्सा आना
या चिंता महसूस करना



सोने में परेशानी
या डरावने सपने आना



विद्यालय या दोस्तों से
दूरी बनाना



बिना बताए चोट लगना

यदि कोई बच्चा बाता करता है तोः

ये करें:

- ध्यान से सुनें
- उस पर विश्वास करें
- उसे आश्वस्त करें
- उसकी सुरक्षा करें

ये न करें:

- उसे दोष न दें
- डाँटें नहीं
- जबरदस्ती सवाल न करें
- संकेतों को अनदेखा न करें

याद रखें: संकेतों को अनदेखा न करें। सुनें, समर्थन दें और उसकी सुरक्षा करें।

आइए जानें LSUC

कभी-कभी बच्चों को केवल देखभाल और सुरक्षा ही नहीं, बल्कि कानूनी सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है।
बच्चों के लिए कानूनी सहायता को आसान बनाने के लिए, नालसा (बच्चों के अनुकूल कानूनी सेवाएँ) योजना, 2024 के तहत प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई (LSUC) की स्थापना की गई है।



रिंकू: अगर किसी बच्चे को वकील या कानूनी सहायता की ज़रूरत हो, तो वह कहाँ जाएगा?



रिया: इसी काम के लिए जिले में LSUC है।

LSUC क्या है?

LSUC बच्चों को विशेष एवं बच्चों के अनुकूल कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें प्रशिक्षित पैनल वकील और पैरालीगल स्वयंसेवक (PLVs) शामिल होते हैं, जिन्हें बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो या विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने का भी अनुभव शामिल है।

LSUC बच्चों को कहाँ-कहाँ सहायता प्रदान कर सकता है?



पुलिस थाना



बाल न्याय बोर्ड (JJBs)



बाल कल्याण समितियाँ (CWCs)



बाल देखभाल संस्थाएँ (CCIs)



बच्चों की अदालतें



अन्य परिस्थितियाँ जहाँ बच्चे को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

LSUC क्या करता है?

- बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में समझाइश देता है।
- कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराता है।
- बच्चों को आसान और बच्चों के अनुकूल तरीके से कानूनी सेवाओं तक पहुँच दिलाता है।
- आवश्यकता पड़ने पर अन्य सहयोगी सेवाओं से जोड़ता है।

याद रखें

हर बच्चे को ऐसी कानूनी सहायता मिलने का अधिकार है जो सम्मानजनक, समझने में आसान और बच्चों के अनुकूल हो।

LSUC

बच्चों के साथ, उनके लिए कानूनी सहायता

बच्चे की मदद करें

एक भरोसेमंद शिक्षक तक पहुँचने में

यदि कोई व्यक्ति बच्चे को असुरक्षित महसूस कराए या गलत तरीके से छुए, तो बच्चे को **किसी भरोसेमंद शिक्षक को बताना चाहिए।**

सुरक्षित रहें

साहसी बनें

आवाज़ उठाएँ



आवाज़ उठाएँ

TEACHERS OF BIHAR
THE CHANGE MAKERS



न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

TEACHERS OF BIHAR
THE CHANGE MAKERS



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

बी ब्लॉक, भूतल,
प्रशासनिक भवन परिसर,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली–110001

जैसलमेर हाउस,
26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली–110011

वेबसाइट: nalsa.gov.in | ईमेल: nalsa-dla@nic.in

NALSA टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100

बाल हेल्पलाइन नंबर 1098

साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930

Teachers Of Bihar-The Change Makers
www.teachersofbihar.org





Manish kumar
Gopalganj